अन्ना ने दिखाया नया रंग: चल दिया सत्ता के संग ?

नई दिल्ली (म.मो.) 18 नवम्बर को दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की प्रेसवार्ता में एक अन्ना समर्थक भाजपाई द्वारा की गयी बद्तमीज़ी जाहिर करती है कि आम आदमी पार्टी के चुनाव अभियान से भाजपा व कांग्रेस किस कदर बौखला चुकी हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर से चल कर आये नचिकेता नामक इस व्यक्ति ने स्वीकार किया है कि वह भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता एवं अहमदनगर भाजपा का पदाधिकारी है। घटना से एक दिन पूर्व वह दिल्ली आकर एक भाजपा सांसद के घर पर ही ठहरा था तथा गिरफ़्तारी के बाद भाजपा के ही एक नेता ने उसे जमानत पर छुड़वाया।

प्रेसवार्ता कर रहे अरविंद, प्रशान्त भूषण व अन्य पर स्याही फ़ेंकते हुए इस युवक ने इन लोग़ों पर वही आरोप दोहराये जो अन्ना ने हाल ही में लिखे अपने एक पत्र में इन लोग़ों पर लगाये थे। विदित है कि अन्ना बार-बार जब-तब यही बात दोहराते हैं कि अरविंद उनके नाम का इस्तेमाल न करे, उनकी तस्वीर का इस्तेमाल न करे, उनके नाम पर एकत्र हुए पैसे का इस्तेमाल न करे आदि-आदि।

किसी से छिपा नहीं है कि करीब एक वर्ष पूर्व ही अरविंद ने जनलोकपाल आन्दोलन के समय एकत्र चन्दे का पूरा हिसाब-किताब अन्ना को सौप दिया था तथा उनके मंच 'इंडिया अगेंस्ट करप्शन' को भी त्याग कर 'आम आदमी पार्टी' का गठन किया था। राजनीतिक पार्टी गठन की बात भी सार्वजनिक मंच से अन्ना के समक्ष ही स्वीकार हुई थी लेकिन बाद में अन्ना इससे पीछे हट गये।

क्या अन्ना नहीं चाहते कि देश को लूटने वाले राजनीतिक दलों के विरुद्ध आन्दोलन मजबूत हो और जनता की इसमें व्यापक भागीदारी बनें? महात्मा गांधी की

मेरे नाम व तस्वीर का इस्तेमाल तो मैं ही करूँगा

ही तर्ज पर वे भी यही चाहते हैं कि आन्दोलन केवल उनके ही हाथ में रह कर उनके ही इर्द-गिर्द घूमता रहे? क्या वे नहीं जानते हैं कि जनता की व्यापक भागीदारी से मजबूत हुए आन्दोलन में लुटेरे शासक दल तहस-नहस हो जायेंगे।

करीब 2 साल पूर्व चलाया गया जनलोकपाल आन्दोलन अकेले अन्ना का नहीं था। उसके पीछे अरविंद सहित अनेक लोग़ों की कड़ी मेहनत थी। यदि अन्ना को अपने नाम अथवा अपनी शख़्सीयत पर इतना गुमान है तो आज वे एक बार फ़िर दिल्ली में आकर देख लें। वैसे तो उन्हें अपनी औकात का अन्दाज़ा उसी वक्त हो जाना चाहिये था जब वे मुम्बई के आजाद मैदान में धरने पर बैठे और जनता नदारद रही। वहां अरविंद जैसे मजबूत कार्यकर्ताओं की टीम नहीं थी, केवल अन्ना व उनका नाम तथा तस्वीर थी, जिसके आज इस्तेमाल पर उन्हें तकलीफ़ है।

अन्ना को इस बात से भी काफ़ी तकलीफ़ है कि अरविंद ने उनके आरोप-पत्र तथा अपने जवाबों को सार्वजनिक किया। सवाल यह है कि सार्वजनिक क्यों न करें? अन्ना इसे जनता से छिपाना क्यों चाहते थे और अरविंद ने इसे सार्वजनिक क्यों किया? दरअसल भाजपा व कांग्रेस की मिली-जुली साजिश यह थी कि अन्ना के इस बेबुनियाद आरोप पत्र को मतदान से ठीक एक दिन पहले सार्वजनिक करके अरविंद के चुनाव अभियान को बिगाड़ा जाय; और जब तक अरविंद अपनी सफ़ाइयां देंगे और इन बेबुनियाद आरोपों को खंडित करेंगे तब तक मतदान संपन्न हो चुका होगा। लेकिन अरविंद ने अपनी दूरदृष्टि से इस साजिश को समय रहते समझ लिया और सारा षड़यन्त्र सार्वजनिक कर दिया। इस साजिश के विफल होते ही 'आप' विरोधियों ने एक सीडी उछाल दी जिसमें अन्ना व अरविंद कुछ बातचीत करते दिखाये गये हैं। यह सीडी काफ़ी पुरानी बताई जा रही है। इस पर अन्ना की ओर से तुरन्त सफ़ाई भी आ चुकी है कि उन्होंने अरविंद पर कोई आरोप नहीं लगाये तथा उनकी नज़र में अरविंद ईमानदार व चरित्रवान व्यक्ति हैं। यहां प्रश्न यह पैदा होता है कि भाजपा व कांग्रेस के पास चुनाव में और कोई मुद्दा नहीं है क्या जो वे बार-बार अन्ना को बीच में घसीट लाते हैं?

वास्तव में है भी ऐसा ही। भ्रष्टाचार के कीचड़ में डूबे दल पूरा ज़ोर लगा कर भी जब 'आप' एवं अरविंद के विरुद्ध कुछ भी आपत्तिजनक नहीं ढूंढ पाये तो वे रह-रह कर अन्ना को घसीट रहे हैं और बिना किसी बात के बतंगड़ बना रहे हैं। लेकिन 'आप' विरोधियों की सारी साजिश को जनता खासकर दिल्ली की जनता बखूबी समझ रही है। इसके परिणामस्वरूप 'आप' की स्थिति और भी सुदृढ होती जा रही है। 'आप' को लोग कांग्रेस और भाजपा के प्रदूषण के बीच ताज़ी हवा का झोंका मान कर उत्साहित हैं।

अवैध निर्माण: नेताओं व अफ़सरों की लूट का धंधा

फ़रीदाबाद (म.मो.) अवैध कब्जे व अवैध निर्माण कराना नगर निगम के अफ़सरों व उन्हें तैनाती देने वाले नेताओं की लूट-कमाई का एक बड़ा जरिया है। इस जरिये को बनाये रखने के लिये नगर निगम नक्शे पास करने के बजाय आवेदकों को बिना नक्शा पास कराये अवैध निर्माण करने की सलाह देता है। कोई न माने तो उसे नक्शा पास करने की कवायद में इतना तंग किया जाता है कि वह अन्ततः अवैध निर्माण करने को मजबूर हो जाता है।

इसके बाद सिलसिला शुरू होता है निगम कर्मियों की लूट-कमाई का। इस काम के लिये फ़रीदाबाद नगर निगम ने बाकायदा एक डाकू गिरोह रखा हुआ है; जिसका नाम है तोड़-फ़ोड़ दस्ता। पेशेवर बिल्डर तो इस डाकू गिरोह को हरकत में आने से पहले ही इनके ठिकाने पर पहुंच कर लेन-देन करके निपटारा कर लेते हैं। जो स्वतः नहीं पहुंचते या लेन-देन सन्तोषजनक नहीं करते अर्थात मुंह-मांगी रिश्वत नहीं देते उनसे निपटने के लिये नगर-निगम अपने इस डाकू गिरोह को छोड़ देता है। इस गिरोह में हैं एक-दो अफ़सर दो-चार पहलवान, एक जेसीबी मशीन और कुछ दिहाड़ीदार मज़दूर। वक्त जरूरत पुलिस को भी बुला लिया जाता है। ज़्यादा मोटी लूट हो तो एक ड्यूटी मैजिस्ट्रेट भी तैनात करा लिया जाता है।

अव्वल तो इस डाकू गिरोह को देखते ही भवन निर्माता ठीक-ठाक सौदा निपटा कर अपनी जान छुड़ा लेता है। जो न निपटा पाये उसके भवन को थोड़ा-बहुत तोड़-फ़ोड़ दिया जाता है। उसके बाद मजबूरी में फ़ंसा बिल्डर किसी बिचोलिये दल्ले-दलाल के माध्यम से सौदा निपटा कर अपना निर्माण पूरा करता है। नगर-निगम के आज तक के इतिहास में एक भी भवन का उदाहरण ऐसा नहीं मिलता जिसे इस डाकू दस्ते ने तोड़ा हो और वह दोबारा से न बन कर खड़ा हो गया हो।

एक ताजा उदाहरण है 5 एन-3। एनआईटी 5 नम्बर के इस प्लाट में बने पुराने मकान को तोड़ कर नया मकान बनाया जा रहा था। दिनांक 6 नवम्बर को डकैतों के उक्त गिरोह ने अपनी गुंडागर्दी दिखाते हुए इस में कुछ तोड़-फ़ोड़ कर दी तथा आगे काम न करने की धमकी दी। बिल्डर ने जाकर लेन-देन कर दिया और निर्माण कार्य फ़िर धड़ल्ले से शुरू हो गया। पहली छत डाल दी गयी है और इस समाचार के छपने तक दूसरी छत भी डाल दी जायेगी। ऐसे में प्रश्न यह पैदा होता है कि यदि प्लाट पर अवैध निर्माण नहीं हो रहा था तो इस डाकू गिरोह ने इसमें तोड़-फ़ोड़ क्यों करी और यदि निर्माण अवैध था तो अब निर्माण कैसे चल रहा है?

उक्त प्रसंग तो मात्र एक उदाहरण है। सारे शहर में यही खेल चल रहा है। शहर की हर गली-मुहल्ले में छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर निर्माण कार्य नगर निगम के अफ़सरों व नेताओं की लूट का एक प्रमुख स्रोत है। अकेले एन एच-5 में ही गत एक वर्ष में 500 से अधिक फ्लैट बन कर बिक व आबाद हो चुके हैं। इस तरह का प्रत्येक फ्लैट कम से कम एक लाख की रिश्वत दिये बिना नहीं बन पाता। इस हिसाब से निगम की लूट का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। अपने प्लाट में तो लोग बना ही रहे हैं, निगम वालों के आशीर्वाद एवं संरक्षण में, कुछ धंधेबाज़ तो अपने प्लाट के साथ लगती सरकारी ज़मीन पर भी कब्ज़ा करके निर्माण करने में जुटे हैं। उदाहरण स्वरूप 5 नम्बर के एल ब्लाक में प्लाट नम्बर 37 ए की रजिस्ट्री में कुल रकबा 116 वर्ग गज़ है जबकि कब्ज़ा व निर्माण 220 वर्ग गज़ पर है।

इतना ही नहीं प्रशासन द्वारा किसी रिहायशी भवन की निर्धारित ऊंचाई 11 मीटर है जबकि बिल्डर 14 से 15 मीटर तक ऊंचाई लेकर एक-एक अतिरिक्त मंज़िल बनाने से नहीं चूक रहे। इसके अलावा एक प्लाट पर पानी व सीवर के एक-एक कनेक्शन के बजाय चार-चार छः छः तक कनेक्शन (अवैध रूप से) लगाने में किसी को कोई गुरेज नहीं। हां, इन कनेक्शनों की जांच एवं सर्वे करने वाले को जरूर चुग्गा-पानी मुहैया करा दिया जाता है। यह सारी लूट कोई चोरी-छिपे या किसी पर्दे के पीछे न होकर खुले आम हो रही है तथा जनता के जिन चुने हुए प्रतिनिधियों का कर्त्तव्य इसे रोकना व जनता को लुटने से बचाना है खुद इस लूट में शामिल होकर अपना-अपना हिस्सा वसूल कर चुप बैठे हैं।

ईएसआईसी की भर्ती विज्ञापन 7 दिन में चले अढाई कोस

फ़रीदाबाद (म.मो.) बरसों बाद ईएसआईसी अस्पताल (एन एच-3) के चलने की नौबत आई तो उसके आका ही उसे चलने नहीं दे रहे। मई 2011 में ईएसआईसी द्वारा एन एच -3 के अस्पताल को अपने अधिकार में लेने की प्रक्रिया शुरू हो गयी थी। 30 सितम्बर 2013 को यह प्रक्रिया पूरी हो गयी और अस्पताल ईएसआई निगम को मिल गया। उस वक्त से लेकर आज तक निगम इस अस्पताल के लिये एक पूर्णकालिक एम एस (मेडिकल सुपरिंटेंडेंट) तक नियुक्त नहीं कर पाई है।

300 बिस्तरों वाले अस्पताल में 150 डाक्टरों तथा 700 अन्य स्टाफ़ की जगह मात्र 13 डॉक्टर व 120 अन्य स्टाफ़ काम कर रहा है। इसके चलते अब यहां मरीज़ों ने भी आना लगभग बन्द ही कर दिया है। अधिग्रहण करने के 2 माह बाद निगम ने मात्र 24 सीनियर रेजिडेंट्स के आवेदन मांगने का विज्ञापन 29 नवम्बर को जारी किया है। यह भर्ती कब तक हो पायेगी, समय ही बतायेगा।

शेष 15 सीनियर रेजिडेंट्स तथा 24 जूनियर रेजिडेंट्स तथा नर्सों व अन्य स्टाफ़ के आवेदन आमन्त्रित करने में निगम और कितना समय लेगी कहना कठिन है। दरअसल निम को चलाने वाले अफ़सर एवं राजनेता इतने संवेदनहीन हैं कि उन्हें उन मज़दूरों की रत्ती भर भी चिंता नहीं है जिनके खून पसीने की कमाई से काटे गये पैसे से वे वेतन तथा ऐशो-आराम की अन्य सुविधायें नियमित रूप से गटक रहे हैं।

संवेदनहीनता व मूर्खता का आलम यह है कि इस अस्पताल में एक हड्डी विशेषज्ञ डॉक्टर को प्रति दिन केवल 4 घंटे के लिये रखा हुआ है। ये डॉक्टर अपने काम में अति निपुण हैं तथा दिल् ली के उसी सफ़दरजंग अस्पताल में हड्डियों की शल्य चिकित्सा कर के सेवानिवृत्त हुए हैं जहां ईएसआई वाले अपने मरीज़ों को रैफ़र करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ईएसआई अस्पताल में आकर लाचार हैं, बेहतरीन शल्य चिकित्सा करने की निपुणता एवं इच्छा के बावजूद भी ये साहब यहां बैठकर केवल रैफ़र करने का ही काम कर पाते हैं, क्योंकि इस अस्पताल में वे साज़ो-सामान एवं उपकरण ही नही हैं जिनकी शल्य-चिकित्सा में आवश्यकता होती है यह ईएसआई अधिकारियों की नालायकी और बदनीयती नहीं तो और क्या है कि शहर के प्राइवेट अस्पतालों में अपने मरीज़ों को रैफ़र करके उन्हें ज़लील कराते हैं और लाखों के बिल अदा करते हैं लेकिन अपने अस्पताल में थोड़ा सा सामान नहीं मंगा सकते।

डीईओ रेखा धारीवाल की बर्खास्तगी टली

दिनांक 23 अक्टूबर को हरियाणा सरकार की ओर से फ़रीदाबाद की पूर्व तथा मेवात की मौजूदा डी ई ओ रेखा धारीवाल को बर्खास्तगी का नोटिस दिया गया था। विदित है कि धारीवाल पर फ़र्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर नौकरी पाने का आरोप लगा था। सरकारी जांच में आरोप सही पाये जाने के बाद ही उक्त नोटिस जारी किया गया था।

यद्यपि फ़र्जीवाड़ा करने वाली धारीवाल के पास अपनी सफ़ाई में कहने लायक कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी बर्खास्तगी रोक दी गयी है। आगामी एक-दो माह में वह सेवानिवृत भी हो जायेंगी। जानकारों का मानना है कि मुख्यमंत्री हुड्डा से कोई रिश्तेदारी निकाल कर उसने अपनी बर्खास्तगी को तो फ़िलहाल बचा लिया है। लेकिन 'मज़दूर मोर्चा' ने इस बाबत आर टी आई आवेदन लगा कर सरकार से आवश्यक जानकारी आवेदन मांग ली है। इसके बाद ही पता चल पायेगा कि कौन-कौन अधिकारी और इस लपेटे में आयेंगे।

ओमप्रकाश वाल्मीकि को विनम्र श्रद्धांजलि

पखवाड़े 17 नवम्बर को हिंदी के जाने-माने साहित्यकार ओमप्रकाश वाल्मीकी का देहरादून में लम्बी अस्वस्थता के बाद निधन हो गया। 63 वर्षीय वाल्मीकि कुछ समय से कैंसर पीड़ित थे और गत वर्ष उनका एक बड़ा आपरेशन भी हुआ था। हिन्दी साहित्य में उनके द्वारा लिखित आत्मकथा 'जूठन' को दलित अस्मिता को रेखांकित करने वाला अद्भुत दस्तावेज माना जाता है। दलित लेखकों की कई पीढियों ने उनके लेखन से प्रेरणा ली। हिन्दी साहित्य पर उनके समग्र प्रभाव का पूर्ण मुल्यांकन अभी बाकी है।